



पंचदश बिहार विधान सभा  
घोडश सत्र  
ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकरण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-13.03.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अरुण शंकर प्रसाद, संविंश०	"राज्य में किडनी रोगियों के इलाज के लिये सरकार द्वारा हयमैन आर्मेन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994 लागू होने के बाद विगत दो वर्ष पूर्व इसकी नियमावली लागू की गयी थी। इन दो वर्षों में पी०एम०सी०एच० एवं आई०जी०आई०एम०एस० जैसे संस्थानों के प्रयास के बावजूद किडनी प्रत्यारोपण का कार्य नहीं किया जा सका। यहाँ के चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। अभी तक इस मद में राशि का आवंटन नहीं हो पाया है। क्रोनिक किडनी रोग से देश में प्रत्येक दस में से एक व्यक्ति पीड़ित है। इस अनुपात में राज्य के एक करोड़ से ज्यादा की आबादी इस रोग से पीड़ित है। किडनी रोगियों का उपचार मुविधा मुहैया करने हेतु हर जिला अस्पताल में पौंच बेड का डाईलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा हुई, परन्तु अधिकतर अस्पतालों में डाईलिसिस सुविधा शुरू नहीं हो सकी है जिसके कारण मरीजों की मृत्युदर में बढ़ि हो रही है जबकि 12 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है।	स्वास्थ्य
	श्री राम नरेश यादव, संविंश०	अतः राज्य में किडनी रोगियों के इलाज के लिये डाईलिसिस एवं किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शोप्र मुहैया कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"	
	श्री विनय कुमार सिंह, संविंश०		
	श्री अरुण कुमार सिन्हा, संविंश०		
	श्री परमानन्द ऋषिदेव, संविंश०		
	ज्ञानचन्द्र माङ्गी, संविंश०		

1	2	3	4
2. श्री अब्दुल बारी सिंहिको, स०वि०स० श्री सदानंद सिंह, स०वि०स० श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, स०वि०स०	“गरीबों को सस्ते एवं मुफ्त अनाज देने के लिए सरकार खाद्य निगम, पैक्स एवं अन्य माध्यमों से धान का क्रय करती है और वही धान मिलरों को दिया जाता है लेकिन वर्ष 2011 से 2014 तक 03 लाख 44 हजार 757 मिट्रोक टन धान राज्य के विभिन्न गोदामों में पड़े रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि मिलरों द्वारा धान नहीं लेने के कारण इन्हें धान जिसकी लागत लगभग 210 करोड़ है, गोदाम में पड़ा रह गया। यह एक गंभीर मामला है जिसकी जाँच आवश्यक है। धान के गोदामों में पड़े रहने के रहस्य पर से पर्दा उठना आवश्यक है।”	एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

हरेराम मुखिया  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/15- 425 / विंस०, पटना, दिनांक- 12 मार्च, 2015 ई०।  
प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं गन्धीपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिविकाता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/15- 425 / विंस०, पटना, दिनांक- 12 मार्च, 2015 ई०।  
प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।